बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 100 ● नई दिल्ली ● बुधवार 28 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

एसिड अटैक के मामलों में सुप्रीम आदेश: कितने मामले अभी लंबित और कितनों पर एफआईआर ? राज्यों से मांगा पूरा ब्योरा

नई दिल्ली । देशभर में एसिड अटैक के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सामने आई है। कोर्ट ने देश में एसिड अटैक की घटनाओं को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें साल-दर-साल एसिड अटैक की घटनाओं का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं। इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय यह भी जानकारी मांगी है कि इनमें कुल कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, कितने मामलों का ट्रायल कोर्ट में निपटारा हो चुका है और कितने मामले अभी लंबित हैं। इसके अलावा अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह विवरण भी देने को कहा है कि एसिड अटैक से जुड़े मामलों में अपील कितनी बार दायर की गई, जिनमें हाईकोर्ट सहित अन्य अपीलीय अदालतें शामिल हैं।

दिल्ली-एनसीआर में तूफानी बारिश बनी आफत

नई दिल्ली । मंगलवार सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शहर के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट और अन्य इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें लगातार बारिश और संभावित व्यवधान के बारे में निवासियों को चेतावनी दी गई है। मौसम संबंधी चेतावनी दोपहर 1:30 बजे तक मान्य है, और आईएमडी ने यात्रियों और निवासियों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश से राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता में राहत मिलने की उम्मीद है, जो मंगलवार सुबह फिर से अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी, सीपीसीबी के समीर ऐप पर एक्यूआई 310 दर्ज किया गया था। यह इस सप्ताह की शुरुआत में लगभग एक दिन की बारिश के बाद कुछ समय के लिए सुधार के बाद हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले एक घंटे में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ गरज, बिजली और ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

मौसम विभाग ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, शाहदरा और पूर्वी दिल्ली में मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछार की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में दिन के दौरान

आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। अकासा एयर, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रा संबंधी सलाह जारी कर यात्रियों से दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा से पहले आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। एयरलाइंस ने यह भी चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब मौसम की स्थिति के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 281 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले राजधानी में शुक्रवार मौसम में हुए बदलाव के साथ हवा की दिशा बदलने और गति तेज होने के चलते लोगों को प्रदूषित फिजा से राहत मिली थी। हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई थी। शनिवार को 192 तो रविवार को 152 एक्यूआई दर्ज किया गया था। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह दिल्ली के अलीपुर में 362, आनंद विहार में 362, अशोक विहार में 348, आया नगर में 230, बवाना में 309, बुराड़ी में 309, और चांदनी चौक इलाके में 319 एक्यूआई दर्ज किया गया है। डीटीयू इलाके में 313, द्वारका सेक्टर-8 में 312, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 में 188, आईटीओ में 312, जहांगीरपुरी में 367, लोधी रोड में 184, मुंडका में 314, नजफगढ़ में 223, नरेला में 286, पंजाबी बाग में 337, आरकेपुरम में 317, रोहिणी में 359, सोनिया विहार में 332, विवेक विहार में 356, और वजीरपुर में 363 एक्यूआई दर्ज किया गया है। यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। 101-200 का मतलब वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब और 301 से 400 के बीच का अर्थ वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। 401 से 500 की श्रेणी में वायु की गुणवत्ता गंभीर बन जाती है। ऐसी स्थिति में इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचता है। पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह जानलेवा है।

दिल्ली में 13 जिलों के लिए लिंक अधिकारियों की नियुक्ति, अब डीएम की गैरहाजिरी में भी नहीं रुकेगा काम

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है. राजधानी में हाल ही में गठित किए गए सभी 13 जिलों के लिंक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. प्रत्येक जिले के लिए दो-दो लिंक अधिकारी तय किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो. सरकार द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अवकाश पर रहते हैं या किसी कारण से अनुपस्थित होते हैं, तो उस जिले का कामकाज पहला लिंक अधिकारी संभालेंगे. वहीं, यदि डीएम के साथ-साथ पहला लिंक अधिकारी भी अनुपस्थित हैं, तो दूसरे लिंक अधिकारी को उस जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इस तरह दिल्ली के सभी 13 जिलों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. खास बात यह है कि सभी लिंक

अधिकारी दूसरे जिलों के डीएम ही नियुक्त किए गए हैं, जिससे अनुभव और प्रशासनिक समझ का लाभ मिल सके. दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने पर जोर दिया है. राजधानी में लंबे समय से यह समस्या चली आ रही थी कि राजस्व पुलिस और अन्य विभागों की जिला सीमाएं अलग-अलग थीं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इस समस्या पर सालों तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के गठन के तीन महीने के अंदर ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अलग-अलग एजेंसियों के जिलों की सीमाओं का एक समान न होना प्रशासन और जनता दोनों के लिए बड़ी चुनौती है. अपनी घोषणा के अनुरूप सरकार ने जिलों का पुनर्गठन किया और दिल्ली में 13 जिले बनाए गए. जिलों की संख्या में बदलाव होने के कारण मार्च 2024 में जारी अधिसूचना में भी संशोधन किया गया है. इसके तहत लिंक ऑफिसर की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब हर जिले के लिए दो लिंक अधिकारी अनिवार्य रूप से तय किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति या अवकाश के दौरान कामकाज निर्बाध चलता रहे. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई सरकार ने जिलाधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां दी गई हैं. इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं. सरकार चाहती है कि डीएम अपने जिले की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहें और योजनाओं व व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से लागू करें. सरकार का मानना है कि मजबूत जिला प्रशासन ही सुशासन की नींव होता है. लिंक अधिकारियों की यह नई व्यवस्था उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे दिल्ली के लोगों को तेज, सरल और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें.

उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में हाईलेवल मीटिंग

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में खरगे तथा राहुल गांधी के अलावा पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, राय के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राय के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक में राय विधानसभा के अगले साल प्रस्तावित चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तथा संगठन को मजबूत बनाने जैसे कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

दिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर, रेखा गुप्ता सरकार ने किया इस बड़े कदम का ऐलान

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर रोजगार की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवा प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इमर्सिव टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह केंद्र विशेष रूप से एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा. यह पहल देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा देगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार फिल्म प्रौद्योगिकी पर भी एक नीति तैयार कर रही है. ताकि यहां की रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके और उन्हें रोजगार के लिए अन्य शहरों या देशों में जाने की जरूरत न पड़े. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की रचनात्मक प्रतिभाओं को पलायन करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली AVGC क्षेत्र के माध्यम से रोजगार की राजधानी के रूप में उभरेगी.मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिससे उनकी विशेषज्ञता और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. यह केंद्र न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर देगा, बल्कि दिल्ली को रचनात्मक और तकनीकी उद्योगों में अग्रणी बनाने में मदद करेगा. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि यह पहल दिल्ली को एक वैश्विक तकनीकी और रचनात्मक केंद्र के रूप में स्थापित करें. इससे युवाओं की प्रतिभा का सही इस्तेमाल होगा और दिल्ली में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी वालों के अछे दिन, सीएम रेखा ने 327 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली।

झुग्गी बस्तियों में लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने 327 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें से 144 करोड़ रुपये के काम आवंटित कर दिए गए हैं।

नए शौचालय बनाने, गलियों की दशा सुधारने सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास जनसेवा सदन में झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उनके क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन, पिछली सरकारों ने उन्हें केवल वोट बैंक की तरह देखा। वर्तमान सरकार उन्हें सम्मान और बेहतर सुविधाएं देना चाहती है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री करोड़ों के शीशमहल में रहते थे, वहीं वर्तमान सरकार जनता के संघर्षों को अपना मानकर दिन-रात उनकी सेवा में समर्पित है सरकार ने बजट में झुग्गी विकास के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किया है। अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य व पोषण जैसी समर्पित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में अब भाजपा की डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। उन्होंने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपेश ठाकुर भी उपस्थित थे। जनसुविधा परिसरों के कुल 476 कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इनमें से 214 कार्यों के लिए 81 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। सड़क व गलियों से संबंधित 254 कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 172 कार्यों के लिए 63 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित किए गए हैं।

दिवालियापन की ओर बढ़ रही है

जल है तो जीवन है-यह पंक्ति कोई नारा भर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का शाश्वत सत्य है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। किंतु विडंबना यह है कि जिस जल को हम जीवन का आधार मानते हैं, वही आज सबसे अधिक संकटग्रस्त संसाधन बन चुका है। देश-दुनिया में जल संकट के हालात विकराल हो चुके हैं और यह संकट अब केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही, भ्रष्टाचार और मूल्यहीन शासन का भी परिणाम बनता जा रहा है। विश्व स्तर पर लगभग 25 देश अत्यधिक जल तनाव से जूझ रहे हैं। चार अरब से अधिक लोग वर्ष में कम से कम एक माह पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र इस संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां 60 करोड़ से अधिक लोग उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे महानगरों में पानी की कमी रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। दरअसल, जल संकट अब 'वाटर स्ट्रेस' से आगे बढ़कर 'ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी' यानी दुनिया जल के वैश्विक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। स्थिति यह है कि जल स्रोतों का दोहन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि उनकी प्राकृतिक भरपाई असंभव होती जा रही है। भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, नदियां सूख रही हैं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। यह संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी है। जल संकट का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा-तीनों ही क्षेत्र पानी पर निर्भर हैं। जब खेतों को पानी नहीं मिलता, उद्योग ठप होते हैं और बिजली उत्पादन प्रभावित होता है, तो देश की जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आमजन के लिए यह संकट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। जहां पानी पर्याप्त है, वहां बर्बादी हो रही है और जहां पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय बनाया है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में ऐतिहासिक पहल हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। अटल भूजल योजना भूजल के सतत प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के संकल्प को साकार करने का प्रयास है। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। इन योजनाओं ने निश्चित रूप से जल संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। कई क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनी हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा मिला है और भूजल पुनर्भरण के प्रयास हुए हैं। लेकिन इस सकारात्मक तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है- प्रशासनिक भ्रष्टाचार। यही वह दीमक है जो इन योजनाओं की उपयोगिता और प्रासंगिकता को नष्ट कर रही है, उन्हें खोखला बना रही है। जल संकट से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखाई देता है-घटिया निर्माण, फर्जी आंकड़े, अधूरी परियोजनाएं, कमीशनखोरी और जवाबदेही का अभाव। कहीं कागजों में ही वर्षा जल संचयन संरचनाएं बन जाती हैं, तो कहीं पाइपलाइन बिछाने में घटिया सामग्री का उपयोग होता है। कई स्थानों पर योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। परिणाम यह होता है कि करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन न पानी मिलता है, और न संकट कम होता है। भ्रष्टाचार केवल धन की बर्बादी नहीं करता, वह भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार भी छीन लेता है। इन जटिल होती जल संकट स्थितियों के प्रति नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को बूंद-बूंद के लिये तरसना पड़ेगा। जल जैसे जीवनदायी संसाधन के साथ किया गया भ्रष्टाचार वास्तव में मानवता के साथ अपराध है। जब जल संरक्षण की योजनाएं कागजों में सिमट जाती हैं, तब जल संकट और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि आज योजनाएं तो हैं, नीतियां भी हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, अतिदोहन, अनियोजित शहरीकरण और कमजोर प्रबंधन इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोका गया, तालाब पाट दिए गए और जंगलों का विनाश किया गया। परिणामस्वरूप वर्षा का पैटर्न बदल गया और जल स्रोत सूखते चले गए। यह स्पष्ट है कि केवल सरकारी योजनाओं से ही समाधान संभव नहीं, जब तक समाज स्वयं जिम्मेदारी न ले। दुनिया के अन्य देशों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इजराइल में ड्रिप इरिगेशन और डिसेलिनेशन तकनीक से 90 प्रतिशत तक पानी का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वाटर ट्रेडिंग के माध्यम से जल संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया गया है। अमेरिका में अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और यूरोप में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जल संकट से निपटने के प्रभावी उपाय बने हैं। भारत में भी राजस्थान जैसे राज्यों में जोहड़, खादिन और बावड़ियों जैसी पारंपरिक जल संरचनाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। समाधान का रास्ता स्पष्ट है-कठोर नीतियां, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी। जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार के प्रति ''जीरो टॉलरेंस'' नीति अपनानी होगी। तकनीक का उपयोग कर निगरानी और सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य बनाना होगा। आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वर्षा जल संचयन, जल की बचत, ड्रिप सिंचाई और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय और समाज

अभी हम अपना 77वां गणतन्त्र दिवस मना चुके हैं जिसमें भारत के शौर्य से लेकर इसकी शक्ति व प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। निश्चित रूप से हमने आजादी के बाद से चहुंमुखी विकास किया है जिसकी छाप राष्ट्र के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। परन्तु कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब इसमें रहने वाले लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और सशक्त बनते हैं क्योंकि वही देश मजबूत होता है जिसके लोग मजबूत होते हैं। देशों का निर्माण चूंकि इसमें रहने वाले लोगों से ही होता है अतः यह बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी देश के लोगों के बीच आपसी भाईचारा व सौहार्द इस प्रकार हो कि हर किसी के प्रगति करने में किसी प्रकार की कोई सामाजिक व आर्थिक बाधा न हो। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि उस देश के लोग शिक्षित व स्वस्थ हों। इस बारे में लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनी गई सरकारों की विशेष भूमिका होती है क्योंकि सरकारी नीतियों से ही किसी भी देश में शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी तय की जा सकती है। अतः स्वतन्त्र भारत में शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए शिक्षा के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान दिया और निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। भारतीय समाज चूंकि जातिगत व्यवस्था के चलते ऊंच-नीच के भाव से ग्रस्त था अतः ऐसे समाज में शिक्षा का प्रसार करके जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। समाज के सभी वर्गों के समुचित विकास के लिए यह बहुत जरूरी था कि स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में सामाजिक रूप से अगड़े-पिछड़े व दलित-सवर्ण में बंटे समाज को शिक्षा के माध्यम से एक समान बनाया जाये और सभी अमीर व गरीब विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर की शिक्षा प्रणाली विकसित की जाये। इस काम में हम उस सीमा तक सफल नहीं हो सके जिसकी अपेक्षा स्वतन्त्र भारत के निर्माताओं को थी। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह रही कि जमीन तक जड़ें जमाए हुए सामाजिक वर्जनाओं की विसंगतियां हमारे शिक्षण संस्थानों तक में पहुंची जिसके कारण समाज के सदियों से शिक्षा से वंचित लोगों के साथ सम्यक रूप से न्याय नहीं हो सका। इसके लिए स्वतन्त्र भारत की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लोगों को आरक्षण देकर यह तय किया कि वे जीवन में तरक्की करने से किसी से पीछे न रह पायें। आर्थिक रूप से भी देश की सरकारों ने इस वर्ग के विद्यार्थियों को समर्थन दिया और सुनिश्चित किया कि वे आर्थिक कठिनाइयों के चलते शिक्षा से वंचित न रह सकें। मगर इसके लिए यह बहुत जरूरी था कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में छात्रों में आपस में बराबरी का भाव जागृत हो और नई पीढ़ियां ऊंच-नीच की मानसिकता से मुक्त हों। इसे समाप्त करने के लिए ही

हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों में दलित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जिससे इस समाज के लोग भी देश की शासन व्यवस्था में सक्रिय योगदान देकर एक समानता की मानसिकता को बढ़ावा दे सकें और नई पीढ़ियां जाति के स्थान पर योग्यता का सम्मान कर सकें, परन्तु 1991 से भारत की अर्थव्यवस्था में बाजारवाद के पदार्पण के बाद सबसे बड़ी विसंगति शिक्षा के क्षेत्र में ही उत्पन्न हुई और निजी क्षेत्र में कथित उच्च गुणवत्ता के स्कूल व कालेजों व विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। इससे शिक्षा के संस्थान दुकानों में तब्दील होने लगे और खासतौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज के धनी वर्ग का आधिपत्य स्थापित होने लगा। मगर 1990 में ही मंडल आयोग के लागू होने की वजह से एक और विसंगति पैदा हुई तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। इसका असर पूरे समाज पर चहुं दिशा पर पड़ा और स्वतन्त्र भारत में एक बार फिर जातियों के आधार पर इसके नागरिकों की पहचान होने लगी। बाद में मनमोहन सरकार के दौरान मानव संसाधन मन्त्री बने स्व. अर्जुन सिंह ने उच्च शिक्षा में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। लोकतन्त्र में वोट की राजनीति के प्रभावी होने की वजह से इस कदम का समर्थन देश की जातिमूलक राजनैतिक पार्टियों ने तो किया मगर वे यह भूल गईं कि भारतीय संविधान जिस जातिविहीन समाज का आह्वान करता है उस दिशा में यह कदम कितना खतरनाक और शिक्षा के क्षेत्र में विभाजन पैदा करने वाला था। वास्तव में यह कदम उठाकर अर्जुन सिंह ने बाजारवाद के समक्ष हथियार डाल दिये थे और शिक्षा के क्षेत्र को निजी धन्ना सेठों की जागीर बनाये रखने के इन्तजाम बांध दिये थे। बाद में 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली में यह संशोधन भी किया गया कि हर उच्च शिक्षण संस्थान में अनुसूचित वर्ग के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए स्थापित तन्त्र में पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया जायेगा। इससे भारत की उस ऐतिहासिक सचाई को नजरअन्दाज किया गया जिसके कारण आज के वर्तमान युग में भी गांवों में दलित समाज के लोगों के साथ भारी भेदभाव किया जाता है। दलित वर्ग के लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पीड़न कथित पिछड़े समाज की दबंग जातियों के लोगों के द्वारा ही किया जाता रहा है। स्वतन्त्रता के बाद से भारत में जिस प्रकार औद्योगिकरण बढ़ा है उसकी वजह से इसके शहरों में जातिगत भेदभाव को हाशिये पर डाला जाने लगा था क्योंकि महानगरों की भाग-दौड़ भरी जिन्दगी में श्रम की महत्ता को स्थान मिलने लगा था जिसकी वजह से व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका श्रम व हुनर बनने लगी थी। हमारे विश्वविद्यालयों में भी अगर जाति के आधार पर ही छात्रों के साथ भेदभाव के भाव को आधार बनाया जाता है और दलितों के समकक्ष ही पिछड़े वर्गों को भी रखा जाता है तो इससे समाज में कलुषता को ही और बढ़ावा मिलेगा और विश्वविद्यालय भी जातिवादी राजनीति का अखाड़ा बनते चले जाएंगे।

सम्पादकीय...

तेल मत देखो, तेल की धार देखो!

उस दिन सुबह सुबह पत्नी ने महीने के राशन की लिस्ट पकड़ाई और बोली, यह आते हुए बाजार से लेते आना। मैंने लिस्ट पढ़ी तो देखा, लिस्ट में खाने का तेल सिर्फ 200 ग्राम लिखा है। मैंने पूछा, इस बार खाने का तेल सिर्फ 200 ग्राम लिखा है। क्या पुराना वाला अभी बचा हुआ है जो इतना कम मंगा रही हो। अरे नहीं, वह तो परसों ही खत्म हो गया था। वह तो मैं जैसे तैसे काम चला रही हूं। तो फिर सिर्फ 200 ग्राम तेल क्यों? अरे, तुम्हें नहीं पता। वह जो ट्रम्प है ना। वही अमेरिका वाला। अमेरिका का राष्ट्रपति। वह ना तेल के पीछे पड़ा है। जहां देखता है, तेल यादा है, वहां कब्जा कर लेता है और वहां के सर्वेसर्वा को हथकड़ी लगा कर अमेरिका ले जाता है। उसकी फोटो नहीं देखी हथकड़ी लगी हुई। मुझे तेल की नहीं, तुम्हारी चिंता है। और मुझे भी साथ ले गया तो। वो पढ़ा नहीं, वेनेजुएला वाले की तो पत्नी को भी साथ ले गया था। देखो, तुम चिंता मत करो। एक तो यह वह तेल नहीं है जिसके पीछे अमेरिका पड़ा है। दूसरी बात, दो चार लीटर तेल इतना नहीं है कि अमेरिका उसे जब्त करने हमारे घर तक आए। और तीसरी बात उसे कैसे पता कि हमने इतना तेल खरीदा है। और यह भी कि हमारे घर में इतना तेल है। यह तो तुम रहने ही दो जी, पत्नी जी ने कहा, पहली बात तो तेल तेल है कोई सा भी हो। दूसरी बात, ठीक है वेनेजुएला में बहुत अधिक तेल है पर जब अधिक वालों पर कब्जा हो जायेगा तो छोटों की बारी भी तो आएगी ही ना। और तीसरी बात, अमेरिका को कैसे पता कि हमारे यहाँ कितना तेल है। तो उसके जासूस तो सब जगह फैले हुए हैं। उसकी सीआईए सब जगह मौजूद है। कहते हैं कुछ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के ऑफिसों तक में उसकी सीआईए मौजूद है। और एक चौथी बात और, यह जो तुम गाड़ी का टैंक फुल करवाते हो ना। आगे से मत करवाया करो। उसमें भी खतरा है। वह तो वही तेल है ना, जिसके पीछे अमेरिका पड़ा है। अरे मैडम, तुम भी बेकार के चक्कर में पड़ी हो। ये तीस पैंतीस लीटर पेट्रोल के चक्कर में अमेरिका पीछे नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारी सरकार जरूर पीछे पड़ सकती है। ईडी और इनकम टैक्स जरूर पीछे पड़ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाते हो, हर हफ्ते तीन हजार का तेल डलवाते हो। इतनी गाड़ी क्यों चलाते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किन किन गतिविधियों में शामिल हो। इस पेट्रोल की फंडिंग कहाँ कहाँ से हो रही है। किसी हवाला रैकेट में तो शामिल नहीं हो, आदि, आदि, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये लोग, ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जरूर मेरे आठ दस घंटे खराब कर सकते हैं। मुझे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की धाराएं लगा, जेल में डाल सकते हैं। चलो जी ठीक है, लेकिन अब तुम आगे से गाड़ी में एक बार में एक हजार से अधिक का पेट्रोल मत डलवाना। अमेरिका से मत डरो, पर अपनी सरकार से तो खौफ खाओ, पत्नी जी ने समझाया, अमेरिका से तो सरकार डर लेगी। और सुनो जी, ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या बला है, श्रीमती जी ने पूछा, वही ना जो जमीन के नीचे से निकलता है, जैसे सोना, चांदी, हीरे वगैरह। इसके पीछे भी तो अमेरिका पड़ा है। वैसे हमें इसका क्या डर। मायके से सोना मिला नहीं, सासूजी ने चढ़ाया नहीं और तुमने दिलवाया नहीं। मुझसे तो अधिक चिंता तो गुमाइन को होगी। डर

दावोस में जाकर देसी कंपनियों से करार

वेनेजुएला के बंधक बनाए गए राष्ट्रपति का भी उन्होंने सड़कछाप भाषा में मजाक उड़ाया है। दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी वे अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। अब उन्हें दूसरे देशों के नेता भी उनकी ही भाषा में जवाब देने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परोक्ष रूप से गुंडा कहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने संबंधी ट्रंप के धमकी भरे बयानों के संदर्भ में मैक्रों ने कहा है कि दुनिया अब गुंडा युग की ओर बढ़ रही है और फ्रांस इस गुंडागर्दी का मुकाबला करेगा। इसी तरह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियेन ने थोड़ी सभ्य भाषा में कहा कि वे कसम खाती हैं कि यूरोप की प्रतिक्रिया बिना डरे बराबरी की होगी। अमेरिका और यूरोप के नेताओं की इस बयानबाजी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय नेताओं की तुलना पालतू जानवरों से की है। उन्होंने कहा है कि ये सब जो बढ़-चढ़ कर बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद सबके सब अपने मालिक यानी ट्रंप के चरणों में लोटते और पूंछ हिलाते दिखेंगे। ट्रंप सचमुच मालिक की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया जा सकता है, जो 'घर में घुस कर मारूंगा', 'मिट्टी में मिला दूंगा' जैसे डायलॉग बोलते रहते हैं। इसके अलावा वे अपने विरोधी नेताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं।

दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कई वजहों से मजाक का विषय बना। इस प्रतिनिधिमंडल में चार केंद्रीय मंत्री, छह मुख्यमंत्री और उनके भारी भरकम लाव-लश्कर के साथ ही सौ से ज्यादा बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मजाक इस बात को लेकर हो रहा है कि भारत से पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कारोबारियों ने वहां आपस में ही निवेश के करार किए हैं। न तो सरकारों का करार विदेशी कंपनियों के साथ होता दिखा है और न देसी कंपनियों का दुनिया के दूसरे देशों के साथ करार हुआ है। दावोस से जो तस्वीरें आई हैं उनमें दो की बड़ी चर्चा है। एक तस्वीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोढ़ा समूह के साथ करार करने की है तो दूसरी तस्वीर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टाटा समूह के साथ करार की है। इसमें फडणवीस और लोढ़ा समूह का मामला बेहद दिलचस्प है। गौरतलब है कि लोढ़ा समूह के प्रमोटर मंगल प्रभात लोढ़ा भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और मुंबई में ही मुख्यमंत्री के निवास से कुछ दूरी पर रहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि मुख्यमंत्री और लोढ़ा के बेटे को दावोस जाकर समझौता करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने वहां अडाणी समूह के साथ भी छह लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर झारखंड सरकार ने टाटा समूह के साथ 11 हजार करोड़ रुपये का एक एमओयू साइन किया है। सोचने वाली बात है कि टाटा समूह की सबसे बड़ी इस्पात फैक्टरी झारखंड में है लेकिन झारखंड सरकार दावोस जाकर करार कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी सैल्फ के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। आंखों से लेजर लाइट निकलने वाली उनकी सैल्फ भाजपा इकोसिस्टम के लोग खूब शेयर करते हैं। लेकिन जयशंकर अपने तेवर दिखाने के लिए बड़ी सावधानी से देशों का चयन करते हैं। अभी उन्होंने पोलैंड के सामने तेवर दिखाए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे तो जयशंकर ने उनसे कहा कि उनका देश पाकिस्तान के साथ ज्यादा नजदीकी दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों के इकोसिस्टम को प्रमोट करता है और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलवाता है। उन्होंने पोलैंड को इससे दूर रहने को कहा। लेकिन ऐसे ही तेवर जयशंकर अमेरिका, रूस और चीन के सामने नहीं दिखाते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान से इन दिनों सबसे ज्यादा करीबी अमेरिका दिखा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बुला कर व्हाइट हाउस में सम्मानित किया। मुनीर को ट्रंप ने लंच कराया और महान जनरल बताया। चीन और रूस से भी पाकिस्तान की दोस्ती खूब बढ़ी हुई है। चीन तो पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने खुल कर पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन भारत की ओर से जिस तरह की चेतावनी पोलैंड को दी गई वैसी चेतावनी कभी भी अमेरिका, चीन और रूस को नहीं दी जाती है। भारत की ओर से नहीं कहा जाता है कि ऐसा मत करो क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी देश है।

हमारे विदेश मंत्री के सारे तेवर छोटे देशों के लिए आरक्षित हैं। एक तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि हैं जो अभिभाषण पढ़े बगैर ही विधानसभा से निकल जाते हैं तो इस बार केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अलग ही कमाल किया। उन्होंने अभिभाषण पढ़ा लेकिन उसके दो हिस्से छोड़ दिए और चले गए। उनके चले जाने के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि राज्यपाल ने पैरा नंबर 12 का शुरुआती हिस्सा और पैरा नंबर 15 का आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ा है। इन दोनों पैराग्राफ में केंद्र सरकार की और उसकी खुद की आलोचना की गई है। उनके चले जाने के बाद इसे पढ़ा गया और सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया। सोचने वाली बात है कि इस तरह की बातों से क्या हासिल होता है? बहरहाल, पैराग्राफ नंबर 12 में सरकार ने लिखा है कि केरल में कई तरह के नीतिगत सुधार हुए हैं लेकिन तमाम नीतिगत और संस्थागत उपलब्धियों के बावजूद केंद्र सरकार के विपरीत कदमों से केरल को वित्तीय मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इसमें आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार का रवैया संघवाद के खिलाफ है। इसके बाद पैरा 15 में विधानसभा में पारित हुए विधेयकों को रोके जाने का जिक्र है। गौरतलब है कि केरल में कई बार इसको लेकर टकराव हुआ है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। पिछले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के समय से ऐसा हो रहा है कि विधानसभा से पारित हुए कई विधेयक राजभवन में अटक जाते हैं। केरल सरकार का कहना है कि इससे जन कल्याण के काम प्रभावित होते हैं। हाल के दिनों की दो घटनाएं और उन पर दो अदालतों का निर्देश यह संकेत देता है कि केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पवित्र गाय है। वह जो चाहे करे, उसे करने की इजाजत है लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ कुछ करेगा तो उसकी खैर नहीं है। एक मामला पश्चिम बंगाल का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरा मामला झारखंड का है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। असल में झारखंड में ईडी की टीम ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया। बाद में कर्मचारी ने ईडी पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर राज्य की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वह व्यक्ति सचमुच घायल हुआ था। लेकिन ईडी के वकील की याचिका पर हाई कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी और झारखंड पुलिस को फटकार भी लगाई। ऐसे ही कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रबंधक के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के दौरान हुए घटनाक्रम का मामला है। उस मामले में राज्य की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों, कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। पहले भी इस तरह के मामले जब भी आए हैं और तब अदालतों ने ईडी को दूसरी एजेंसियों के ऊपर प्राथमिकता दी है। हालांकि ईडी को लेकर कई बार अदालतों ने सख्त रुख दिखाया है और उसके कामकाज पर सवाल उठाए हैं लेकिन दूसरी एजेंसियों के साथ विवाद की स्थिति में हमेशा ईडी को प्राथमिकता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्तरहीन भाषा से तो दुनिया वाकिफ ही है। वेनेजुएला के बंधक बनाए गए राष्ट्रपति का भी उन्होंने सड़कछाप भाषा में मजाक उड़ाया है। दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी वे अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। अब उन्हें दूसरे देशों के नेता भी उनकी ही भाषा में जवाब देने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परोक्ष रूप से गुंडा कहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने संबंधी ट्रंप के धमकी भरे बयानों के संदर्भ में मैक्रों ने कहा है कि दुनिया अब गुंडा युग की ओर बढ़ रही है और फ्रांस इस गुंडागर्दी का मुकाबला करेगा। इसी तरह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियेन ने थोड़ी सभ्य भाषा में कहा कि वे कसम खाती हैं कि यूरोप की प्रतिक्रिया बिना डरे बराबरी की होगी। अमेरिका और यूरोप के नेताओं की इस बयानबाजी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय नेताओं की तुलना पालतू जानवरों से की है। उन्होंने कहा है कि ये सब जो बढ़-चढ़ कर बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद सबके सब अपने मालिक यानी ट्रंप के चरणों में लोटते और पूंछ हिलाते दिखेंगे। ट्रंप सचमुच मालिक की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया जा सकता है, जो 'घर में घुस कर मारूंगा', 'मिट्टी में मिला दूंगा' जैसे डायलॉग बोलते रहते हैं। इसके अलावा वे अपने विरोधी नेताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं।

वित्त व्यवस्था को ख़तरनाक रास्ते पर धकेला जा रहा है

भाजपा-नीत सरकार ने अभी पिछले ही दिनों संसद से एक कानून बनवाया है, जो भारत के बीमा क्षेत्र में 100 फीसद तक विदेशी हिस्सा पूंजी की स्वामित्व की इजाजत देता है। प्रधानमंत्री ने एलान किया है कि यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक बड़े 'सुधार' की शुरुआत का सूचक है। अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कथित सुधार हमारी वित्तीय संस्थाओं में और बढ़ा निजी स्वामित्व का-जिसमें विदेशी स्वामित्व भी शामिल है-रास्ता खोले जाने की ही दिशा में जाएगा। निस्संदेह यह इस क्षेत्र के प्रति, स्वतंत्रता के बाद के दौर में अपनायी गयी नीति के उल्लेखनीय रूप से पलटे जाने का ही सूचक है। आईएमएफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की विभिन्न अन्य एजेंसियां और अमेरिकी प्रशासन, लंबे अर्से से वित्तीय क्षेत्र के प्रति नीति में इस तरह के बदलाव की मांग करते आ रहे थे। वास्तव में अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो भारत सरकार को यह सुझाव भी दिया था कि चाहे फौरन समूचे वित्तीय क्षेत्र का निजीकरण संभव नहीं हो, सरकार सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक का निजीकरण करने के जरिए, इस तरह का 'एक संकेत तो दे ही सकती' थी। बहरहाल, नव-उदारवादी 'सुधारों' के अपने शौक के बावजूद, कांग्रेस-नीत सरकार इस ख्याल से ही ठिठक गयी। लेकिन भाजपा, जो कि भारतीय कॉर्पोरेट स्वार्थों की ओर भी निर्मम चाकर है, जबकि इन स्वार्थों का अब वैश्वीकृत पूंजी के स्वार्थों के साथ कमोबेश मेल ही बैठ चुका है, साम्राज्यवादियों के मांगे इन 'सुधारों' को लागू करने की तैयारियां कर रही है। यानी वित्तीय क्षेत्र को निजीकरण तथा विदेशी प्रभुत्व की उसी दिशा में धकेला जा रहा है, जिस रास्ते से उसे स्वतंत्रता के बाद छुड़ाया गया था। और वित्तीय क्षेत्र को इस रास्ते से छुड़ाए जाने के बहुत पुख्ता कारण थे और इन कारणों की पड़ताल करना उपयोगी हो सकता है। पहला तो यही कि वित्तीय बाजार, 'उत्पादन' और 'सट्टे' में भेद नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है। अगर किसी परिसंपत्ति को 'रखने' के लिए यानी इससे समय के साथ आय के जिस प्रवाह का अनुमान है उसके लिए खरीदा जाता है, तो इसे 'उत्पादन' के लिए खरीदना कहा जाएगा। लेकिन, अगर किसी परिसंपत्ति को इसी उद्देश्य से खरीदा जाता है कि उसे जल्द ही बढ़े हुए दाम पर बेच दिया जाए, उस स्थिति में खरीददार की उस परिसंपत्ति से आने वाली आय में तथा इसलिए इससे शामिल होने वाले उत्पादन की धारा में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसे 'सट्टेबाजारी' कहते हैं। चूंकि निजी वित्तीय संस्थाएं, जो पूरी तरह से मुनाफे के ख्याल से ही संचालित होती हैं, इन दो अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों में अंतर ही नहीं करती हैं और इसलिए अपने संसाधनों का एक हिस्सा, उत्पादन की बलि देकर सट्टेबाजी में फंसाए रखती हैं, तीसरी दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था शायद ही कभी इस तरह का रास्ता लेना चाहेगी। दूसरे, उत्पादन के दायरे में भी, निजी वित्तीय संस्थाएं ऋण देने के मामले में, सुव्यवस्थित तरीके से विभिन्न ऋण-ग्राहकों के बीच अंतर करती हैं। औपनिवेशिक दौर में, जब भारतीय उद्यमी बैंकों के पास ऋण लेने के लिए जाते थे, ये बैंक चूंकि बहुत हद तक विदेशी स्वामित्व में थे, वे भारतीय उद्यमियों के साथ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव किया करते थे। वक्त के साथ, भारतीय कारपोरेट घरानों ने अपने बैंक स्थापित कर लिए, ताकि अपने कारोबारों के लिए वित्त जुटा सकें। लेकिन, वे खुद अन्य ऋण-ग्राहकों को ऋण के दायरे से बाहर रखते थे। खासतौर पर छोटे उत्पादकों, किसानों, दस्तकारों और ऐसे ही अन्य तबकों को, संस्थागत वित्त के इन स्रोतों के दायरे से बाहर ही रखा जाता था। चूंकि वित्त, पूंजी पर नियंत्रण को प्रदर्शित करता है, इस वित्त का किस प्रकार से वितरण होता है यानी यह वित्त किसे मिलता है, किन क्षेत्रों में यह वित्त जाता है, किन गतिविधियों के लिए इस वित्त का उपयोग होता है, उससे देश में विकास की दर और विकास का पैटर्न तय होता है। और चूंकि निजी वित्तीय संस्थाएं, व्यवस्थित तरीके से बहिष्करण का सहारा लेती हैं और कुछ खास क्षेत्रों को तथा संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय उत्पादकों को ऋण के दायरे से बाहर रखा जा रहा होता है, यह न सिर्फ विकास के पैटर्न को विकृत करने का काम करता है बल्कि विकास को बाधित भी करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वित्त को सट्टेबाजी के बजाए उत्पादन के लिए ही लगाया जाना है, अगर उसे कृषि तथा लघु उत्पादन जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए लगाया जाना है, तो वित्तीय संस्थाओं पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था, इस काम को पूरा करने में पूरी तरह से अक्षम है। इस काम के लिए यानी एक ऐसा आर्थिक विकास करने के लिए, जो संतुलित हो तथा कुछ खास सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा करता हो, वित्तीय संस्थाओं पर राजकीय स्वामित्व जरूरी हो जाता है। यही बुनियादी अंतर्दृष्टि थी जो 'नव-उदारवादी' सुधारों के आने से पहले तक के भारतीय विकास यात्रापथ के पीछे रही थी। इसी के चलते 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था; 1956 में जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया था; 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में छह अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वित्तीय क्षेत्र पर राजकीय स्वामित्व की दिशा में इसी बदलाव का एक और नतीजा, कृषि की ओर अभूतपूर्व तरीके से संस्थागत वित्त का प्रवाह होने के रूप में सामने आया था और इसी ने हरित क्रांति को और खाद्यान्न के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता को संभव बनाया था। साठ के दशक के आरंभ में भारत, अमेरिका से खाद्यान्न के आयात पर निर्भर हो गया था और इस तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद के हथकंडों के लिए वेध्य हो गया था। इसी संदर्भ में भारत का खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना एक उल्लेखनीय कारनामा था, जिसे पलटवाने की साम्राज्यवाद की कोशिशें आज तक जारी हैं। यह भी वित्तीय क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व की प्रधानता का ही नतीजा था कि जब अमेरिका में आवासन का बुलबुला फूटा था और पूंजीवादी दुनिया की समूची वित्त व्यवस्था संकट में चली गयी थी, उस समय भारत उन चंद देशों में था, जो इस संकट से कमोबेश अछूते रह गए थे। आईसीआईसीआई बैंक के अपवाद को छोड़कर, भारतीय बैंकों के पोर्टफोलियो में विदेशी परिसंपत्तियां बहुत थोड़ी ही थीं और शायद ही कोई विषाक्त परिसंपत्तियां रही होंगी। इस तरह राजकीय स्वामित्व ने करोड़ों जमाकर्ताओं की जमाराशियों को खतरे में पड़ने से बचा लिया था।

आर्थिक उदारीकरण ने एक हद तक, भारत की वित्तीय व्यवस्था के स्वास्थ्य को, पहले के मुकाबले कमजोर कर दिया है। बेशक, किसानी खेती में खपने लगने वाले संस्थागत वित्त का परिमाण बहुत ही घट गया है और तरह-तरह के बिचौलिये निकल कर आ गए हैं, जो बैंकों से ऋण उठाते हैं और फिर यही पैसा कहीं ज्यादा ब्याज पर और वास्तव में अनाप-शनाप ब्याज पर, किसानों को मुहैया कराते हैं। लेकिन, भाजपा-नीत सरकार तो इस क्षेत्र की बची-खुची स्वस्थता को भी खत्म कर देना चाहती है और वह ऐसा करना चाहती है, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के निजीकरण तथा उसमें विदेशी दबदबे की प्रक्रिया को तेज करने के जरिए। बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सा पूंजी की अधिकतम सीमा को खत्म ही करने के लिए सरकार की ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं, उन पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। एक दलील तो यही है कि इससे बीमा क्षेत्र में और ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा और इससे बीमा सुरक्षा की पहुंच तथा गुणवत्ता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। लेकिन, अगर भारतीय बीमा उपभोक्ताओं से जमा किए जाने वाले पैसे का उपयोग विदेश में सट्टा बाजारों के उद्यमों में ही किया जा रहा होगा, तब तो इससे न तो भारत के विकास में कोई मदद मिलने वाली है और न ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाने में। इसी प्रकार इस दावे में भी दम नहीं है कि इसके चलते उपभोक्ता अब सोने तथा अचल संपत्ति जैसी परिसंपत्तियों में अपनी दौलत रखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे बल्कि अपनी दौलत बीमा पॉलिसियों में रखेंगे और यह वित्त को उत्पादक कार्यों की ओर ले जाने का काम करेगा। लेकिन, इस दलील का तब क्या अर्थ रह जाएगा जब, जिसकी कि ज्यादा संभावना है, इस वित्त को सट्टेबाजाराना उद्देश्यों की ओर मोड़ा जा रहा होगा या उसका उपयोग, अपने से छोटे उद्यमों का अधिग्रहण करने या मुनाफों का हिस्सा बढ़ाने तथा इस प्रक्रिया में मुद्रास्फीति को भड़काने के जरिए, इजारेदारियों की सेवा करने के लिए किया जा रहा होगा। बेशक, हो सकता है कि सरकार यह उम्मीद लगाए बैठी हो कि उसके इस बीमा 'सुधार' से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के खिलाड़ियों का 'भरोसा' बढ़ेगा और इस तरह वित्त का इस समय जो पलायन हो रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ फेसलाइन एम्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

एसवाईएल कैनाल पर सकारात्मक उम्मीद, श्रुति चौधरी ने कहा - भाईचारे से हल निकलेगा

जींद ।

सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक) कैनाल विवाद पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच हुई वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन भाईचारे के बीच पानी के मुद्दे का हल होना चाहिए। श्रुति चौधरी ने कहा, एसवाईएल का मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। पानी कितना बड़ा मुद्दा है, भाईचारे के बीच पानी के मामले का हल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हरियाणा का एसवाईएल के पानी पर अधिकार है। हमें लगता है इस मामले में अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। उन्होंने

दक्षिण हरियाणा में पहले होने वाले भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले पावर वाले लोग ही पानी ले आते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में सभी को पानी मिल रहा है। सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा काम टेल तक पानी पहुंचाना है। उन्होंने याद दिलाया कि चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में रेतीले इलाकों को नहर का पानी देने के लिए कैनाल-नहरों का निर्माण हुआ था। राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा, राजनीति लोगों की सेवा का माध्यम है। हरियाणा विकास पार्टी में मेरे स्वर्गीय दादा बंसीलाल ने काम किया। कांग्रेस पार्टी को मैंने अछे से देखा है। भाजपा का पक्का कार्यकर्ता हूं।

कांग्रेस पार्टी इतनी गई-गुजरी हो चुकी है कि ना तो नेता हैं, ना नियति। लोग बस भ्रमित करने का काम करते हैं। वोट चोरी को मुद्दा बनाए हुए हैं। पूरे हरियाणा के लोगों से पूछ लो, अगर कहीं वोट चोरी हुई हो तो बताएं, कांग्रेस के लोग ऐसी बातें करते हैं जो गले नहीं उतरतीं। यह बयान ऐसे समय आया है जब एसवाईएल कैनाल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों रायों के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई और आगे संवाद जारी रखने पर सहमति बनी। मंत्री श्रुति चौधरी के इस बयान से हरियाणा में एसवाईएल के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है।

यूजीसी एक्ट के विरोध में बीजेपी नेत्री ने दिया इस्तीफा, कहा- इससे बढ़ेगी असमानता

बहादुरगढ़ ।

यूजीसी एक्ट 2026 को संविधान के अनुछेद 14 के खिलाफ बताते हुए भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता मनीषा शर्मा ने पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में असमानता बढ़ाने वाला है। मनीषा शर्मा गांव खरहर की निवासी हैं और बूथ अध्यक्ष, छरा मंडल की मंडल सचिव व मकण्डल महिला मोर्चा के अध्यक्ष जैसे पदों पर रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि संविधान व शिक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है। अपने पत्र में मनीषा शर्मा ने कहा है कि यूजीसी एक्ट 2026 शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर की भावना को कमजोर करता है और इससे सामाजिक व शैक्षणिक असमानता बढ़ने की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह कानून उस मूल भावना के खिलाफ है। मनीषा शर्मा लंबे समय से भाजपा से जुड़ी हैं और संगठन में विभिन्न दायित्व निभा चुकी हैं। मनीषा शर्मा ने कहा कि उनका यह निर्णय किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि संविधान और शिक्षा के व्यापक हित में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करे।

हरियाणा में 5 आईएएस, 1 आईआरपीएस अधिकारी का तबादला

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 आईएएस और एक आईआरपीएस अधिकारी के स्थानांतरण एव नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। श्री सुधीर राजपाल, जो अब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, को गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है। गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। श्री अरुण कुमार गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे, को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव तथा वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री साकेत कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हरियाणा, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव लगाया गया है। उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा नगर निगम आयुक्त, पंचकूला श्री राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। आईआरपीएस अधिकारी श्री विनय कुमार, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, को नगर निगम, पंचकूला का आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का विशेष कार्य अधिकारी लगाया गया है।

भाजपा इस देश की मिट्टी से जुड़ी पार्टी है, कांग्रेस धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही : अनिल विज

चंडीगढ़ । हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राय सरकार द्वारा बजट से पूर्व सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की परंपरा एक सशक्त और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचायक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके। इस दिशा में आज विज द्वारा राय के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का बजटीय प्रावधान तथा इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव दिया गया है। अनिल विज आज पंचकूला में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में सांसदों एवं विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने सुझावों में प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, जिसमें सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सहित निजी

स्कूल, कॉलेज एवं गौशालाएं शामिल हैं, की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल स्वछ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली खर्च में भी कमी आएगी और हरियाणा हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होगा। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव भी दिया, ताकि आमजन का रुझान पर्यावरण अनुकूल ई-वाहनों की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व राय राजमार्गों के किनारे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए, जहां वाहन चार्जिंग के साथ-साथ यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट, स्वछ शौचालय और आराम की समुचित व्यवस्था हो, जिससे परिवारों को यात्रा के दौरान सुविधा मिले। विज ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशभर में लोगों से संवाद कर बजट संबंधी सुझाव ले रहे हैं और इसी कड़ी में सभी सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया था, किंतु विपक्ष का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि संभवतः विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पहले ऐसी बैठकों में विपक्ष भाग लेता रहा है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को सम्मान न मिलने से जुड़े प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और उसका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा हाल ही में कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने कहा कि अंग्रेज और मुगल इसलिए चले गए क्योंकि वे विदेशी थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की मिट्टी से जुड़ी पार्टी है और इसी धरती पर जन्मी है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की संस्कृति, राष्ट्रभाव और विचारधारा को आगे लेकर चल रही है। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में एक विदेशी अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा अंग्रेजों के साथ तालमेल के लिए की गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि विदेशी दलों के जाने की बात है तो कांग्रेस जाएगी, भाजपा नहीं, क्योंकि भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी।

हरियाणा में महिलाएं सेफ : पुलिस का दावा महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी आई; दुष्कर्म व किडनैपिंग के मामले घटे

चंडीगढ़ ।

हरियाणा पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाए गए विशेष अभियानों, सघन निगरानी और प्रभावी पुलिसिंग के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वर्ष 2024 की तुलना में 16.26 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो महिलाओं में बढ़ते सुरक्षा विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि महिला सुरक्षा हरियाणा पुलिस की हमेशा प्राथमिकता रही है और वर्ष 2025 में महिला विरुद्ध अपराध में दर्ज की गई गिरावट इस बात का प्रमाण है कि पुलिस की योजनाएं, फील्ड एक्शन और तकनीकी उपाय प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में हरियाणा पुलिस का विज़न महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ महिलाओं में निर्भीकता और विश्वास की भावना को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। डीजीपी ने महिला विरूद्ध अपराध में कमी लाने के लिए प्रदेशभर में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें उनके समर्पण, कर्तव्यनिष्ठ और निरंतर प्रयासों के लिए बधाई दी तथा महिलाओं से अपील की कि वे पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। सीसीटीएनएस के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गंभीर अपराधों में भी स्पष्ट कमी दर्ज की गई है। दुष्कर्म के मामलों में लगभग 25 प्रतिशत, दुष्कर्म के प्रयास के मामलों

में 33 प्रतिशत, छेड़छाड़ के मामलों में करीब 16 प्रतिशत, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में लगभग 10 प्रतिशत, अपहरण व किडनैपिंग के मामलों में 17 प्रतिशत से अधिक तथा दहेज हत्या जैसे संवेदनशील अपराधों में 11 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। महिला विरुद्ध अपराध के निपटारे के स्तर पर भी हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी रही है। वर्ष 2025 में महिला विरुद्ध अपराध की वर्कआउट दर लगभग 98 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2025 में प्रदेश भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। इसके अंतर्गत छेड़छाड़ संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।

स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंडों, बाजारों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस टीमों द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बल मिला है। इतना ही नहीं, प्रदेश में महिलाओं के साथ संभावित छेड़छाड़ वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची तैयार कर वहां साधारण वेशभूषा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, ताकि मनचलों की पहचान कर उनको सबक सिखाया जा सके। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिसमें महिला विरुद्ध अपराध की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं से संवाद तथा फीडबैक आधारित पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया गया। महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं हरियाणा 112 के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत कर इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, जिसके तहत महिला के सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने तक उसकी निगरानी की जाती है। सिंघल ने प्रदेश की आम जनता से अपील की है कि महिला सुरक्षा को लेकर समाज की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है इसलिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, बदतमीजी, हिंसा या महिला विरुद्ध अपराध की जानकारी तुरंत हरियाणा 112 या नजदीकी पुलिस थाना को दें और पीड़ित महिला का मनोबल बढ़ाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी पहलों एवं पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग करें, ताकि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

सफदरजंग एन्क्लेव में कांस्टेबल पर हमला, लूटी पिस्टल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने और उसकी सरकारी पिस्टल लूटकर फरार हुए दो बदमाशों को पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टुंडला पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन में मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ जानू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथी वसीम को बाद में दबोचा गया.दरअसल, 22 जनवरी 2026 को दोपहर करीब सवा 2 बजे सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में बीट ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार को एक राहगीर ने पार्क के पास इलाके में मौजूद दो संदिग्ध लोगों की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर पुलिसकर्मी ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया. एक आरोपी ने सिपाही को काबू में लिया, जबकि दूसरे ने उसकी सर्विस पिस्टल छीन ली. इतना ही नहीं उसने पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानकर धमकी भी दी और हवा में फायरिंग कर मौके से भाग गया. गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. वारदात के बाद पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी एक बाइक सवार को जबरन रोककर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाईं. टीमों ने सफदरजंग एन्क्लेव, हौज खास, मालवीय नगर, महरौली समेत आसपास के इलाकों के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए एक आरोपी की पहचान अविनाश उर्फ जानू के रूप में हुई, जो पहले भी दिल्ली में लूट और स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल रहा है. जांच में पता चला कि आरोपी दिल्ली से फरार होकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला इलाके में छिपा हुआ है. वहीं 23 जनवरी 2026 को दिल्ली पुलिस और टुंडला पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश में दबिश दी. दोपहर करीब 2:15 बजे आरोपी को टुंडला इलाके में एक स्कूटर पर जाते हुए देखा गया.

पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो तेज रफ्तार में भागने लगा. लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा. खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. गोलियां पुलिस की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के घुटने में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपी अविनाश उर्फ जानू से पुलिस ने लूटी गई 9 एमएम की सरकारी पिस्टल, तीन खोखे, एक स्कूटर और मोबाइल फोन बरामद किया. पूछताछ में उसने सफदरजंग एन्क्लेव की घटना में अपनी भूमिका कबूल की और बताया कि उसका साथी वसीम भी इस वारदात में शामिल था. आरोपी की निशानदेही और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने 23 जनवरी की रात करीब 11:42 बजे मालवीय नगर के स्वामी नगर इलाके में कब्रिस्तान के पास से उसके साथी वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक 30 साल का अविनाश उर्फ जानू दिल्ली में लूट और स्नैचिंग के 10 से ज्यादा मामलों में शामिल रह चुका है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

प्रोटोकॉल उल्लंघन पर भड़के खरगे- कहा-

गणतंत्र दिवस परेड में उचित सम्मान नहीं, विपक्ष के अपमान पर सरकार दे जवाब

नई दिल्ली।

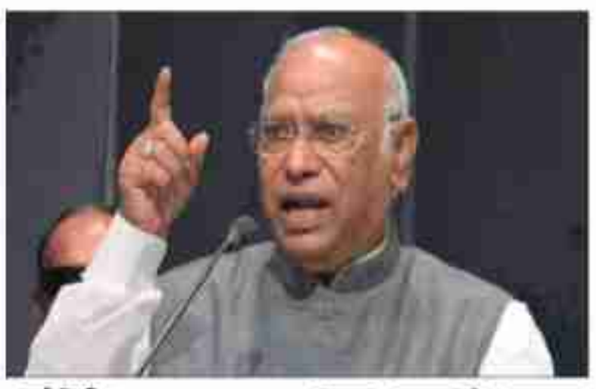

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बैठने की व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में विपक्ष के नेताओं का अपमान किया गया है। खरगे के अनुसार, सरकार ने जानबूझकर प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी की और विपक्षी नेताओं को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं।

खरगे ने कहा- विपक्ष के नेताओं का हुआ अपमान

अपनी बात रखते हुए खरगे ने कहा कि वह देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उनके और राहुल गांधी के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से कैबिनेट रैंक वाले नेताओं को पहली कतार में जगह मिलनी चाहिए। इसके बावजूद, उन्हें समारोह में तीसरी लाइन में बैठाया गया। खरगे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस लाइन में उन्हें जगह दी गई, वहां राज्य मंत्री और बच्चे बैठे थे।

पास मिलने में हुई परेशानी

कांग्रेस अध्यक्ष ने पास मिलने में हुई परेशानियों का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने सचिवों को भेजकर बैठने की जगह की जानकारी जुटानी पड़ी। उन्हीं सचिवों ने काफी कोशिशों के बाद पास का इंतजाम किया। खरगे ने सरकार के इस व्यवहार को सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि देश के संविधान और पूरे विपक्ष का अपमान बताया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह इस अपमानजनक व्यवहार पर स्पष्ट जवाब दे।

हरियाणा में बजट सत्र की तैयारी, 2 फरवरी को कैबिनेट की अहम बैठक; मुख्यमंत्री सैनी तय करेंगे तारीख

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख की घोषणा हो सकती है। इस बार राज्य सरकार की योजना बजट सत्र जल्दी शुरू करने की है। संभावना है कि 22 फरवरी के बाद किसी भी समय बजट सत्र शुरू हो सकता है। विधानसभा सचिवालय की तैयारियों से लग रहा है कि बजट सत्र 23 फरवरी अथवा 26 फरवरी से आरंभ हो सकता है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक दो फरवरी को शाम चार बजे होगी। इस बैठक का परिपत्र मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। मंगलवार को मुख्य सचिव भी काम पर लौट आए हैं। हालांकि उनके अभी दफ्तर में बैठने की संभावना कम है, लेकिन वह अपने कैंप आफिस से सभी सरकारी फाइलों का निपटारा करेंगे। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्ष 2026-27 का अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। पिछला बजट दो लाख पांच करोड़ रुपये के आसपास का था, जो कि इस बार करीब सवा दो लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस बार चार मार्च का फाग (होली) है। राज्य सरकार की कोशिश फाग से पहले ही हरियाणा का बजट पेश कर दिए जाने की संभावना है। पिछले साल सात मार्च को राज्य का बजट सत्र आरंभ हुआ था, जो कि 28 मार्च तक चला था। इस बार 20 मार्च तक हर हाल में बजट सत्र समाप्त किया जा सकता है। पिछला इतिहास कहता है कि कम से कम 12 सीटिंग हर बजट सत्र में होती हैं। इस बार 14 सीटिंग होने की संभावना है। बजट पेश होने के बाद उस पर चर्चा के लिए विधायकों की कमेटियां भी बनाई जाएंगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र शुरू होने की सिर्फ तारीख तय की जाएगी। बजट सत्र कितनी अवधि तक चलेगा, इसका फैसला हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किया जाता है।

हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, चार की मौत

उधमपुर। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उधमपुर जिले के शारदा माता के पास हुई, जहां एक बस और एक मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बस उधमपुर की ओर जा रही थी और कथित तौर पर तेज रफ्तार में थी। हादसे की गंभीरता के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसमें बस सवार चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बस सड़क किनारे खड़े महिंद्रा लोड कैरियर की मरम्मत कर रहे दो मैकेनिकों को भी टक्कर मार दी। दोनों मैकेनिकों को भी गंभीर चोटें आईं और वे घटनास्थल पर ही दम तोड़ गए।

नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। यूजीसी के उच्च शिक्षा नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत जिंदल द्वारा दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम - उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम, 2026 - जारी किए हैं। इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना है। यह याचिका रोहित वेमुला और पायल ताडवी की माताओं द्वारा दायर की गई है।

अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले- पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आड़ में एनआरसी करा रही बीजेपी

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अभियान चला रहा है और साथ ही आम जनता को परेशान कर रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि ईसीआई यह एसआईआर अभियान केवल पश्चिम बंगाल के लिए चला रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले छमाही में होने की उम्मीद है। यहीं एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह मतदान में वृद्धि सुनिश्चित करे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा, एसआईआर की आड़ में, एनआरसी चला रहे है और आम जनता को परेशान कर रहे है, और उनका उद्देश्य अधिक वोटों की कटौती करना है। जबकि उनकी जिम्मेदारी मतदाताओं की मदद करना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे देश में अगर कोई भाजपा को टक्कर दे रहा है, तो वह ममता बनर्जी ही है। यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को हराएगी और ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर कोई भाजपा को टक्कर दे रहा है, तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। भाजपा द्वारा लाया गया एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) केवल पश्चिम बंगाल के लिए है, हालांकि इसे बिहार में भी लागू किया गया था। सपा प्रमुख ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाता है, लेकिन एसआईआर के नाम पर ठीक उल्टा हो रहा है। बंगाल में एसआईआर के नाम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है। देश में अतीत में एसआईआर के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया गया। मुझे विश्वास है कि वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। बंगाल की जनता भाजपा को हराएगी। वे हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक वोट काटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी को हरा दिया है। भाजपा पेन ड्राइव कांड के दर्द से उबर नहीं पाई है। एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुनाव आयोग के आचरण से गहराई से व्यथित है और आरोप लगाया कि चुनाव निकाय मतदाता सूचियों में तार्किक विसंगति के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, और यह कितना दुखद तमाशा है! आयोग, जो अपने आकाओं की आवाज बनकर लोगों के मतदान अधिकारों को छीनने में व्यस्त है, मतदाता दिवस मनाने की हिम्मत कर रहा है! मैं आज उनके इस आचरण से अत्यंत व्यथित और विचलित हूं।

भारत का ऊर्जा क्षेत्र 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर देता है : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने वैश्विक निवेशकों से देश में निवेश करने का आह्वान किया। 'भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '' भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसरों की भूमि है क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है। तेल शोधन क्षमता को 26 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 करोड़ मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से सभी क्षेत्रों में सुधार कर रहा है। मोदी ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का पूरक है क्योंकि इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा एवं सेवाओं को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को ''मदर ऑफ ऑल द डील्स (सबसे अहम समझौता) बता रहे हैं। इस समझौते ने 140 करोड़ भारतीयों के साथ-साथ यूरोपीय लोगों के लिए भी कई अवसर उत्पन्न किए हैं। उनके अनुसार, यह दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मोदी ने कहा कि यह समझौता वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा है।

'भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों और नवप्रवर्तकों को एकजुट करने वाला एक प्रमुख वैश्विक मंच है।

देशभर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध

दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी, यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजीं

नई दिल्ली।

देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह-जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।

रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा 'सवर्ण' हूं... मेरा रोंया-रोंया उखाड़ लो राजा। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है- प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र 'स्वाभाविक अपराधी' बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी।

किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा- धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। साथ ही कानून का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। कोई कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जो कुछ होगा संविधान के दायरे में ही होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए एक बात बहुत विनम्रता से स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाएगा। और भेदभाव नहीं होगा। किसी को डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर कोई भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं होगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो इसके दायित्व होगी। मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था हुई है संविधान के परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। मैं आश्वस्त और अपील करना चाहता हूं कि किसी के ऊपर भेदभाव या किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा।

बरेली में बवाल : निलंबित मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की मांग- राष्ट्रपति शासन लागू करो

बरेली।

मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए निलंबित बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन पर उत्पीड़न और जाति आधारित दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठाए और व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मैं जिला मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि उन्हें कल रात किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने के कारण गाली दे रहा है, और वह व्यक्ति किस विचारधारा का है?

संवैधानिक प्रक्रियाओं के टूटने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आम जनता सरकार के खिलाफ हो गई है। यह विरोध प्रदर्शन अग्निहोत्री के नगर मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के शिविर कार्यालय में रात भर बंधक बनाकर रखने की सुनियोजित साजिश रची गई थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया था। जिला मजिस्ट्रेट के शिविर कार्यालय में फोन आया कि इस पंडित को पूरी रात वहीं बैठाकर रखा जाए और उसे कहीं जाने न दिया जाए। अग्निहोत्री ने बताया कि जब उन्हें लगा कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बार एसोसिएशन और मीडिया को सूचित किया। उन्होंने कहा, जब उन्हें पता चला कि मीडिया को मुझे बंधक बनाने की योजना की जानकारी है, तो मुझे जाने दिया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह घटना उन्हें बयान जारी करने के लिए मजबूर करने और फिर अलग आधार पर निलंबित करने की साजिश का हिस्सा थी। जांच की मांग करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि फोन पर हुई बातचीत और उनके निलंबन से जुड़े हालातों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम निलंबन आदेश के संबंध में अदालत में अपील करेंगे और जल्द ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इससे पहले, अग्निहोत्री ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं का हवाला दिया, जिनमें प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुई घटनाएं भी शामिल हैं। अधिकारियों ने अभी तक उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बजट सत्र : सुझावों का स्वागत है, लेकिन हंगामे से बचें- सरकार की विपक्ष को दो-टूक

नई दिल्ली।

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों के सुझाव सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चर्चा संसदीय नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, नियमों के अनुसार, चर्चा सिर्फ बजट पर ही होनी चाहिए। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी, जिसमें सभी दल हिस्सा लेंगे। सरकार हमेशा किसी भी सुझाव को सुनने के लिए खुला है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार हमेशा सुनने को तैयार है, लेकिन अगर हर बार विपक्षी दल हंगामा करते हैं और सदन नहीं चलने देते, तो समस्या पैदा होती है। इसके अलावा, टीडीपी संसदीय दल के नेता लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने बताया कि उनकी पार्टी ने बैठक में तीन राष्ट्रीय मुद्दे और पांच आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाए। इनमें भारत के एफटीए समझौते, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियम और अमरावती राजधानी विधेयक शामिल हैं। पत्रकारों से बातचीत में देवरायलु ने कहा कि हम तीन राष्ट्रीय मुद्दे और आंध्र प्रदेश से जुड़े पांच मुद्दे उठाना

चाहते थे। पहला राष्ट्रीय मुद्दा भारत के एफटीए समझौतों से जुड़ा है, जिसमें भारत-ईयू एफटीए भी शामिल है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। दूसरा मुद्दा 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का है। अगर ऑस्ट्रेलिया यह कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं? राज्य का प्रमुख मुद्दा अमरावती राजधानी विधेयक है। हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी को कानूनी समर्थन मिले। यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में हुई, बजट सत्र की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस बैठक में राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, एआईटीसी नेता शताब्दी रॉय, एमएनएम संस्थापक कमल हासन, तमिल मणिला कांग्रेस नेता जीके वासन, एसपी नेता रामगोपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

1 फरवरी को पेश होगा बजट

बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक। जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। वहीं, 1 फरवरी को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बता दें कि पिछले मानसून और शीतकालीन सत्र 2025 में विपक्षी दलों ने पूरे देश में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की थी।